भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1267
(जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

ग्लोबल नेटवर्क के साथ ईएसजी मानदंडों को संरेखित करने के लिए कदम

1267. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक सीमा से अधिक कारोबार वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बीआरएसआर (व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट) को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है;
(ख) भारत के ईएसजी मानदंडों को आईएसएसबी या ईयू-सीएसआरडी जैसे वैश्विक ढाँचों के साथ संरेखित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) कारपोरेट ईएसजी प्रकटीकरणों में ग्रीनवाशिंग की निगरानी के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार ने स्थिरता अनुपालन पर एसएमई के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): जी नहीं। व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उत्तरदायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) को एमसीए द्वारा संशोधित किया गया था और जिम्मेदार व्यवसाय आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) नामक नए सिद्धांत मार्च, 2019 में जारी किए गए थे। इसके पश्चात, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने एनजीआरबीसी के ढांचे के आधार पर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग प्रारूपों को अंतिम रूप देने के लिए व्यावसायिक दायित्व रिपोर्टिंग पर एक समिति का गठन किया, जिसका एक सदस्य सेबी भी था। समिति की सिफारिशों और व्यापक हितधारक परामर्श के आधार पर, 2021 में, सेबी ने शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण के आधार पर) को वित्त वर्ष 2021-22 से स्वैच्छिक आधार पर और वित्त वर्ष 2022-23 से अनिवार्य रूप से व्यावसायिक दायित्व और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) के अनुसार ईएसजी प्रकटीकरण करने का आदेश दिया। शेष सूचीबद्ध संस्थाएँ, जिनमें एसएमई एक्सचेंज पर अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने वाली संस्थाएँ भी शामिल हैं, स्वेच्छा से व्यावसायिक दायित्व और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का प्रकटन कर सकती हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग ढाँचों के साथ-साथ स्थिरता रिपोर्टिंग में वैश्विक रुझानों पर भी ध्यान दिया है। साथ ही, बीआरएसआर तैयार करते समय भारत की विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को ध्यान में रखा गया था, इसलिए बीआरएसआर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रिपोर्टिंग ढाँचों के साथ अंतर-संचालन की अनुमति देता है, अर्थात वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रिपोर्टिंग ढाँचों पर आधारित स्थिरता रिपोर्ट (वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में) तैयार और प्रकट करती हैं, वे ऐसे ढाँचे के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरणों को बीआरएसआर के अंतर्गत मांगे गए प्रकटीकरणों से क्रॉस-रेफरेंस कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, यदि रिपोर्टिंग प्रारूप में मांगा गया डाटा पहले ही वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जा चुका है, तो सूचीबद्ध संस्था उसका क्रॉस-रेफरेंस प्रदान कर सकती है।

(ग): ग्रीनवाशिंग के जोखिमों को कम करने के लिए, 12 जुलाई, 2023 और 28 मार्च, 2025 के परिपत्रों के माध्यम से, सेबी ने बीआरएसआर कोर की शुरुआत की है, जिसमें महत्वपूर्ण/कोर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) का एक सीमित सेट शामिल है, जिसके लिए सूचीबद्ध संस्थाओं को शीर्ष 150 सूचीबद्ध संस्थाओं (वित्त वर्ष 2023-24 से), शीर्ष 250 सूचीबद्ध संस्थाओं (वित्त वर्ष 2024-25 से), शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं (वित्त वर्ष 2025-26 से) से शुरू होने वाले निर्दिष्ट ग्लाइड पथ के अनुसार आश्वासन/मूल्यांकन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और यह वित्त वर्ष 2026-27 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, सेबी ने वित्त वर्ष 2025-26 से स्वैच्छिक आधार पर शीर्ष 250 सूचीबद्ध संस्थाओं की मूल्य श्रृंखला के लिए ईएसजी प्रकटीकरण और वित्त वर्ष 2026-27 से स्वैच्छिक आधार पर इसका आश्वासन/मूल्यांकन भी शुरू किया है।

सेबी ने (i) 3 फरवरी, 2023 के परिपत्र के माध्यम से कुछ निश्चित कार्य करने और न करने योग्य बातें निर्धारित की हैं, जिन्हें ग्रीन ऋण प्रतिभूति जारीकर्ता को ग्रीनवाशिंग की घटना से बचने के लिए सुनिश्चित करना होगा और (ii) 6 फरवरी, 2023 के परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रीन ऋण प्रतिभूति से प्राप्त आय के उपयोग के बाद के प्रबंधन और आंतरिक ट्रैकिंग और प्रभाव रिपोर्टिंग के सत्यापन के लिए ग्रीन ऋण प्रतिभूति के लिए तीसरे पक्ष के समीक्षक/प्रमाणक की नियुक्ति निर्दिष्ट की है। तीसरे पक्ष के समीक्षक/प्रमाणक की नियुक्ति की उक्त आवश्यकता 01 अप्रैल, 2023 से दो वर्ष की अवधि के लिए 'अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें' के आधार पर लागू है। ये प्रावधान अब 22 मई, 2024 को गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों, प्रतिभूति रसीदों, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों और वाणिज्यिक पत्र के जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए मास्टर परिपत्र के क्रमशः अध्याय IX-क और अध्याय IX में शामिल किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2024 में, सेबी के परामर्श से, स्टॉक एक्सचेंजों के तत्वावधान में, तीन उद्योग संघों अर्थात एसोचैम, सीआईआई और फिक्की के प्रतिनिधियों को शामिल कर उद्योग मानक फोरम ("आईएसएफ") द्वारा बीआरएसआर कोर पर उद्योग मानक तैयार किए गए हैं। मानकों का उद्देश्य बीआरएसआर कोर के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाना, व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देना और बीआरएसआर कोर के कार्यान्वयन में मानकीकरण लाना है। इसके अतिरिक्त, बीआरएसआर कोर के अनुसार, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, शीर्ष 250 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाजार पूंजीकरण के आधार पर) के लिए मूल्य श्रृंखला हेतु ईएसजी प्रकटीकरण, वित्त वर्ष 2024-25 से अनुपालन-या-स्पष्टीकरण के आधार पर शुरू किया गया है। इसका सीमित आश्वासन वित्त वर्ष 2025-26 से अनुपालन-या-स्पष्टीकरण के आधार पर लागू होगा।

(घ): एमएसएमई मंत्रालय विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र योजना "एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ावा देना और उसमें तेज़ी लाना" (आरएएमपी) का कार्यान्वयन करता है। इस योजना के अंतर्गत, एमएसएमई, उद्योग संघों, राज्य सरकार के अधिकारियों और पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक अनुपालन में अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ईएसजी कार्यशालाओं के आयोजन के लिए आरएएमपी के अंतर्गत अनुदान भी प्रदान किया गया है।

****